



सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र



JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 3 JULY TO 9 JULY 2020 • VOLUME- 43 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
No Filing Charges &
*Pay money after the visa

IELTS | STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

किस नोटिफिकेशन के आधीन पी.ए.पी.फलाईओवर पर वाहनों की डिजाइन स्पीड लिमिट को बदला गया ?

नीरज की विशेष रिपोर्ट

जालंधर ब्रीज। जालंधर पानीपत-राष्ट्रीय राजमार्ग को गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाए केंद्र की सरकार। प्रधानमंत्री की इमानदारी अपने ही केंद्र के नेशनल हाईवे विभाग में विफल हो गई ये कोई भी दावा बगैर तथ्यों के साथ नहीं किया जा रहा इसकी हकीकत आपको ग्राउंड जीरो में जाकर इस राजमार्ग के लंबित चल रहे निर्माण कार्यों को देख कर खुद ही पता चल जाएगा।

यह प्रोजेक्ट पिछले तकरीबन 14 वर्षों से लंबित पड़ा है और यह अभी भी आने वाले 4 से 5 वर्षों में पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा इसके लिए ना तो प्रधानमंत्री या इस विभाग के मंत्री की कुशलता पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन्होंने पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में देश के कई प्रोजेक्टों को पूरा कर दिखाया।

परन्तु इस राष्ट्रीय राजमार्ग की देरी के लिए सीधे तौर पर भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेवार हैं जिन्होंने टेका



नेशनल हाईवे विभाग

छाया : रवि

प्राप्त कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिये सरकार में रह कर अपने पद का दुरुपयोग किया और करोड़ों रुपये की बेनामी सम्पत्ति बनायीं और टेका कंपनी को बी ओ टी मॉडल में इस प्रोजेक्ट में रख-रखाव के नाम पर करोड़ों रुपये के टोल टैक्स की आम लोगों से वसूल करवाकर बदले में

लोगों को बनती सुविधाओं से वंचित रखने का काम किया। आज भी हाईवे की हालत इतनी दयनीय है की जगह जगह पर बरसती पानी जमा होने से लोगों की मौत हो रही है, नालियां टूटी पड़ी हैं। पी.ए.पी. फलाईओवर को शुरू

होने के 2 घंटे के बाद ही बंद करना पड़ा था जिसको अब इस गलत बने फलाईओवर को जुगाड़ के साथ दोबारा शुरू करवाया गया है। पिछले दिनों विभाग के चेयरमैन को इसको नए सिरे से 8 लेन करने के लिए निर्देश दिए जिसमें रोजनल ऑफिस द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर



छाया : रवि

जालंधर को संबंधित विभागों से तालमेल करने के लिए जिम्मेवारी सौंपी गयी अब यह फलाईओवर मौजूदा मटेरियल की महंगी कीमतों से बनेगा जिसको की अगर पहले से ही सही बना दिया जाता तो इसको दोबारा ना बनाना पड़ता और पता नहीं लोगों को कितने साल और

परेशान होना पड़ेगा। इसकी लडोवार में विभाग के पेट्रोलिंग अधिकारियों द्वारा विज्ञापन नीति की धजियां उड़ाई जा रही हैं जिसमें उसके द्वारा प्राइवेट हस्पतालों, रेस्टोरेंट वालों के अवैध विज्ञापन लगावाकर उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है और यही नहीं इस के

साथ विभाग के मंत्री की योजनाओं को टेंग भी दिखाया जा रहा जिसमें वो देश में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं ताकि की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बढ़ा कर व्यापार को बढ़ाया जा सके परन्तु विभाग के कुछ अफसरों द्वारा किसी निजी

हॉस्पिटल के विज्ञापन को लगा कर डिजाइन स्पीड लिमिट 90 किलोमीटर प्रति घंटा को घटाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा करने के किसने हुक्म दिए यह सब जांच का विषय है। इस गंभीर मुद्दे पर जालंधर ब्रीज की टीम दुआरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंबाला से ई मेल के माध्यम से संपर्क साधा गया परन्तु उन्होंने ई मेल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा उसके बाद इन सब की गंभीरता को समझते हुए उनसे फोन पर संपर्क साध कर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने संविधानिक पद पर बैठ कर गैर जिम्मेवार बयान देते हुए यह कहा की हमारे पास 600 किलोमीटर की सड़कें हैं और इसके लिये हम दो ही अफसर हैं इसलिए कहाँ क्या हो रहा है।

हम नहीं देख सकते यह जिम्मेवारी टेका प्राप्त कंपनी की है इस जवाब ने उनकी कानलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है और इस बात को हवा दी है कि कहीं टेका प्राप्त कंपनी के साथ उनकी शांमलियत तो नहीं ? यह सब जांच का विषय है।

लोगों की रातों की नींद उड़ा कर खुद मजे से सो रहे हैं बिजली विभाग के अफसर



छाया : रवि

नीरज की विशेष रिपोर्ट जालंधर ब्रीज। वार्ड नंबर 66 की पिछली एक साल से लंबित चली आ रही कम लोड वाले ट्रांसफार्मर की समस्या को दूर करने में इलाके के जूनियर इंजीनियर से लेकर एजीक्यूटिव इंजीनियर तक के अफसरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए उन्होंने जालंधर ब्रीज के संवादाता से बात करते हुए कहा

की हमारी ऊपर के अधिकारी नहीं सुनते हम उनके ध्यान में कई बार यह बात ला चुके हैं पर उन पर कोई असर नहीं है इस बात से यह बात साबित होती है की सरकार के पावर सरप्लस के दावे खोखले हैं और मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट को नगर निगम को जानकारी दिए बगैर रात को स्ट्रीट लाइट बंद रख कर कम लोड वाले लगे हुए ट्रांसफार्मर पर

लोड घटा कर घरों को आधी अंधूरी बिजली दी जा रही है और बिजली के बिल पिछले साल की एवरेज लगा कर लोगों को भेजे जा रहे हैं। कोरोना महामारी ने जहाँ पूरे देश को हिलाके रख दिया है। वही आम लोगों की जेब पर बिजली बिलों का भोज डाला गया है परन्तु अफसर अपने घर में बैठकर आनंद ले रहे हैं क्योंकि उनको तृप्तान आये यान

भूचाल उनको तो सरकार ने पालना है अगर कोई नेता लोगों की मदद करने के लिए आवाज बुलंद करे तो अफसर उसको उकसाकर गुस्से में उससे से कोई गलत काम होने पर उसको डाल बनाकर यूनियन बाजी की ऐवज में उस पर पर्चे डलवा रही है यह कतई बर्दाश नहीं किया जायेगा और जालंधर ब्रीज बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की

हकीकत को उजागर करता रहेगा और जनहित में लोगों को आ रही मुश्किलों के लिए आवाज बुलंद करता रहेगा और कुम्भकर्णी नंद सोये हुए भ्रष्ट उच्च अधिकारियों की रातों की नींद उड़ाने के लिए वचनबद्ध है और पिछले एक साल में कितनी बार पॉवर कट लगे और कयों लगे यह एक जांच का विषय है।

गुरु पूर्णिमा पर चन्द्रग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा

ज्योतिष विशेषज्ञ

ज्योतिष गणानुसार आषाढ़ शुल पक्ष गुरु पूर्णिमा रविवार 5 जुलाई को मनाई जाएगी। चंद्र एवं सूर्य ग्रहण पड़ते हैं। अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण आता है। आषाढ़ शुल गुरु पूर्णिमा रविवार 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। पांच जुलाई को लगने वाला है, यह ग्रहण भी उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इसके अलावा ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस कारण इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं लगेगा। इसलिए इस ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं किए जाएंगे। इस कारण चंद्रग्रहण का कोई सूतक काल (अशुभ काल) नहीं होगा और न ही ग्रहण का किसी राशि पर नकारात्मक असर पड़ेगा। 5 जून से 6 जुलाई के बीच कुल तीन ग्रहण लगे हैं। चामुंडा दरबार के पुजारी गुरुजी पं. रामजीवन दुबे एवं ज्योतिषाचार्य विनोद रावत ने बताया कि सूतक काल जब माना जाता है जबकि चंद्र या सूर्य ग्रहण स्पष्ट दिखाई देवे। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा तो सूतक का प्रश्न ही नहीं है।

गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5 जुलाई को, शिष्य करोगे गुरुओं की पूजा



किन देशों में देखा जाएगा चंद्रग्रहण

5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत, दक्षिण एशिया के कुछ स्थान, अमेरिका, यूरोप और अस्ट्रेलिया में देखा जा सकेगा।

चंद्रग्रहण का समय

यह ग्रहण 5 जुलाई को सुबह 8 बजकर 38 मिनट से आरंभ होगा। इस चंद्र ग्रहण की अवधि 2 घंटा 43 मिनट और 24 सेकंड होगी। भारत में उस समय दिन एवं सूर्य का प्रकाश रहेगा। जबकि यह चंद्र ग्रहण जिन देशों में रात्रि होगी वहां यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा।

क्या होता है

चंद्रग्रहण ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। ग्रहण को ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन पड़ता है। चौथा उप छाया चंद्रग्रहण 29 नवंबर को लगेगा।

चंद्रग्रहण का राशियों पर प्रभाव

मेघ-मान नाश, वृषभ-मृत्युतुल्य कष्ट, मिथुन-स्त्री पीड़ा, कर्क-सौय, सिंह-चिंता, कन्याव्यथा, तुला-श्री, वृश्चिक-क्षति, धनु-घात, मकर-हानि, कुंभ-लाभ, मीन-सुख।

ऐसा देश है मेरा!

सोशल मीडिया से

TIKTOK

सैनिकी शहादत (गलवान)

इस तस्वीर में आज की सच्चाई है!

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह केंद्र की कार्रवाई में नहीं करेगा हस्तक्षेप

नई दिल्ली, (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 34 विदेशी जमातियों की याचिकाओं की सुनवाई शुरू कर दी। 10 जुलाई तक के लिए टालते हुए कहा कि कोर्ट उन्हें स्वदेश भेजने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के मामले पर ही सुनवाई करेगा। इस बीच, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विदेशी जमातियों की स्वदेश वापसी तब तक नहीं हो सकेगी, जब तक उनके खिलाफ भारत के किसी भी राज्य में दर्ज आपराधिक मुकदमों की सुनवाई पूरी

नहीं हो जाती। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाशकालीन खंडपीठ को बताया कि वीजा रद्द करने को लेकर हर विदेशी जमाती के मामले में सरकार द्वारा अलग-अलग आदेश पारित किया गया है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि फिर तो हर प्रभावित जमाती को हाईकोर्ट जाना चाहिए। 34 विदेशी जमातियों ने याचिकाएं दायर कीं औरतलब है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों

याचिकाकर्ता सरकार से करें स्वदेश भेजने की मांग और राज्य सरकारों एवं पुलिस के आदेश का उल्लंघन करने पर हजारों जमातियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई अदालतों में लंबित है। केंद्र सरकार ने हजारों जमातियों को ब्लैक लिस्ट करके उनके वीजा रद्द कर दिए थे, जिनमें से 34 विदेशी जमातियों ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को करने का

निर्णय लिया। इस बीच सरकार जमातियों के बारे में जारी आदेश की कॉपी कोर्ट को सौंपेगी। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि वीजा जारी करना या रद्द करना सरकार का संप्रभु फैसला है। इसमें अदालत दखल नहीं दे सकती। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक मामले में अलग-अलग आदेश जारी किया गया था और इसकी सूचना संबंधित व्यक्तियों को ई-मेल के जरिए दी गई थी।

आपराधिक मामला लंबित याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह दलील दी गई कि वीजा रद्द किए जाने के बाद जमात के विदेशी सदस्यों को उनके देश वापस भेजा जाना चाहिए। ब्लैक लिस्ट में डालने का आदेश तो तब लागू होगा, जब वे दोबारा भारत आना चाहेंगे। इसपर सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है, ऐसे में उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को स्वदेश भेजे जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे स्वदेश भेजे जाने की मांग सरकार से करें, अदालत इसमें दखल नहीं देगी, बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के मामले पर सुनवाई करेगी।

प्रसंग मप्र बना देश का नया अन्न भंडार



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के अन्नदाता किसानों ने ही मध्यप्रदेश को बनाया है। पंजाब जो परंपरागत रूप से गेहूं उत्पादन और उपजर्जन में देश में सबसे आगे होता था वो स्थान आज मध्यप्रदेश ने प्राप्त कर लिया है। इस वर्ष 129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं उपजर्जन कर मध्यप्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है। खेती किसानों मध्यप्रदेश का आधार है। पहले प्रदेश को पिछड़ा माना जाता था। आज प्रदेश के किसानों ने मध्यप्रदेश के भाल पर बंपर उत्पादन का ऐसा तिलक लगाया है कि मध्यप्रदेश सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गया है। देश के कुल गेहूं उपजर्जन में एक तिहाई योगदान हमारे प्रदेश का है। पंजाब जो ऐतिहासिक रूप से गेहूं उपजर्जन में अग्रणी हुआ करता था वह आज मध्यप्रदेश से पीछे हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रयास पहले से ही प्रारंभ किये थे। सिंचाई सुविधाएं बढ़ाकर खेती का सिंचित रकबा बढ़ाया गया। किसानों को रियायती दर पर बिजली दी गई। कोशिश यह की गई कि उत्पादन लागत न्यूनतम हो और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को अत्यंत सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देकर बाजार में अनाज के मूल्य को न्यूनतम स्थिर रखना है। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से स्वयं समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है और राज्य अपनी आवश्यकता के लिए खरीदी करते हैं। कई राज्य देश के अन्य प्रदेशों की आवश्यकता के लिए उपजर्जन करके भारत सरकार को केंद्रीय पूल में सौंप देते हैं। मध्यप्रदेश को अपने लिए 29 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त जो गेहूं उपजर्जन किया है वह केंद्रीय पूल के लिए है। कोविड-19 संकट के कारण गेहूं का उपजर्जन सरकार और किसानों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण था। लॉकडाउन और आवामन बाधित होने के कारण बाजार में गेहूं का विक्रय नहीं होने से सरकारी खरीदी किसानों के लिए बहुत आवश्यक थी। गेहूं उपजर्जन की तैयारियां पहले जैसी नहीं थी। मुख्यमंत्री ने पर संभालते ही उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। मध्यप्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2012-13 से ही ई-उपजर्जन

नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, इसके माध्यम से किसानों के पंजीकरण से लेकर उपजर्जन केंद्रों का निर्धारण, किसानों से क्रय की प्रक्रिया, गोदामों तक ट्रकों से परिवहन, किसानों का भुगतान इत्यादि सभी प्रक्रियाएं पूर्णतः ऑनलाइन हैं। राज्य सरकार ने शुरू से ही गेहूं उपजर्जन की रणनीति के सभी विषयों को बारीकी से समझा और जो भी दिक्कत आ सकती थी उनको दूर किया। उपजर्जन केंद्रों की संख्या दोगुनी कर दी गई। एक तिहाई से अधिक केंद्र गोदाम स्तर पर खोले गए। इसके परिणामस्वरूप किसानों को कम से कम दूरी तक अपनी पड़ी तथा प्रत्येक केंद्र पर कम से कम भीड़ हुई। खरीदी केंद्रों पर स्थानीय लोगों को ही रोजगार देकर श्रमिकों की व्यवस्था की गई। गेहूं परिवहन के लिए ट्रकों की व्यवस्था, गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए चलाए गए लॉजिस्टिक अभियान में दो माह तक 10 हजार से भी ज्यादा ट्रकों का उपयोग कर गेहूं का गोदामों में भंडारण किया गया। पूरे अभियान में 16 लाख किसानों ने उपजर्जन केंद्रों पर अपना गेहूं बेचा और उपजर्जन के संपूर्ण प्रबंधन में 5 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगे। यह अभियान कोरोना और लॉकडाउन के दौर में संभवतः विश्व के सबसे बड़े अभियानों में से एक रहा है। उपजर्जित गेहूं के भुगतान की भी सुनिश्चित व्यवस्था की गई। अभी तक लगभग 25 हजार करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते इस वर्ष गेहूं उपजर्जन कर किसानों को प्राथमिकता के आधार पर राशि दी गई। उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली। गेहूं उपजर्जन की प्रक्रिया में छोटे-छोटे भूखंड पर खेती करने वाले लघु और सीमांत किसानों को सबसे पहले सीधे लाभान्वित करने में सफलता मिली। मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना है। प्रदेश इस दिशा में मजबूती से कदम उठा रहा है। मध्यप्रदेश के किसान मेहनती हैं। उनकी मेहनत ने आज मध्यप्रदेश को यह ऐतिहासिक उपलब्धि दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मेरी सरकार किसानों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी, जिससे भविष्य में भी ऐसी उपलब्धियां हमारे अन्नदाता किसानों के प्रयासों से मिलेंगी। प्रदेश के किसानों ने सरकार के प्रति जो भरोसा दिखाया है, मैं उसे हर हालत में निभाऊंगा। किसान पुत्र मुख्यमंत्री अन्नदाता की समाधान के समाधान के लिए हमेशा सबसे आगे मजबूती से खड़े रहते हैं। किसानों में यह भरोसा

है कि उनका लीड स्वयं किसान है इसलिए किसानों के हितों की अनदेखी कभी भी नहीं हो सकती। कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते किसानों को होने वाली संभावित कठिनाइयों को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूं उपजर्जन का मजबूत नेटवर्क खड़ा किया और किसानों का गेहूं खरीदकर उनके खातों में नकद पैसा डाला। फसल बीमा योजना का पैसा भी जो पहले नहीं मिल पाया था उसे किसानों को दिलाया गया। सरकार के प्रयासों और किसानों की मेहनत से मध्यप्रदेश अनाज उत्पादन में देश का सिरमौर बनता जा रहा है। मार्च माह में कोविड 19 की भयावह तस्वीरों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को सचमुच चिंता में डाल दिया था कि गेहूं तैलना तो दूर खरीदना कौन? व्यापारी क्या बोली लगाने आएंगे? या इस परिस्थिति का फायदा उठा कर कहीं फसल के मूल्य से भी समझौता न करना पड़ जाए। लेकिन उनका खलिहान में पड़ा गेहूं न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ने खरीद लिया बल्कि वो मूंग की फसल पर भी बहुत ज्यादा उत्पादित है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उम्मीद से ज्यादा दिया है सभी किसान खुश हैं, इस अवधि में 129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं समर्थन मूल्य पर उपजर्जित किया गया है। प्रदेश के लिए यह ऑल टाइम रिकॉर्ड है। साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं उपजर्जन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पंजाब को पछड़ते हुए देश में पहले स्थान पर आ गया। कोविड-19 की भयावह तस्वीरों के बीच सत्ता संभालने और इन सबके बीच गेहूं की फसल की चिंता कर लेना काफी नहीं था शायद, जो अचंभे में डलते हुए शिवराज सिंह चौहान के आउट ऑफ द बॉक्स जाकर गेहूं की खरीदारी में प्रदेश को पहले नम्बर पर लाकर खड़ा कर दिया और पंजाब जैसे राज्य को भी पीछे छोड़ दिया। इतनी चुस्त-दुरुस्त सरकारी प्रणाली वाकई उनके राजनीतिक इच्छा शक्ति को न सिर्फ बताती है बल्कि उन लोगों का भी मुंह बंद कर देती है जो गेहूं की फसल को खलिहानों में ही सड़ जाने की आशंकाओं में दुबले हो रहे थे। वाकई इस बात पर सरकार को दाद देना तो बनता है शब्दों की कृपणता और आशंकाओं के पीछे छिप जाने जैसी विधाओं के बावजूद ये रिकॉर्ड तो कबीले तारीफ है। एक व्यावहारिक चुनौती गेहूं का सुरक्षित भंडारण किया जाना था जो कि स्पष्ट आदेशों और पक्की योजना के कारण अमले ने आखिर ये भी कर ही दिखाया।

विचार

चीन की दुखती रग पर हाथ

भारत ने चीन को आर्थिक और सामरिक मोर्चे के बाद अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी घेरा है। अभी तक हॉनग कॉन्ग के मुद्दे पर चुप रहने वाले भारत ने इशारों में चीन को दो टूक सुना दिया है। भारत ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि इसका उचित समाधान हो।



चीन को सबक सिखाने भारत उसे सामरिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर घेर चुका है। अभी तक लद्दाख में हेकड़ी दिखा रहे चीन के 59 एएस पर भारत में बैन लगाने के बाद ड्रेगन हकलाने लगा है। भारत ने चीन को घेरने अब कूटनीतिक हथियार भी उठा लिया और अब तक हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून पर चुपचाप साधने वाले भारत ने इशारों में इस कानून पर सवाल उठाए हैं और दो टूक सुना दिया है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने कहा कि हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया चीन का घरेलू मामला है लेकिन भारत हाल की घटनाओं पर करीबी नजर रखे हुए है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंदर ने कहा, हम हाल की इन घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इन बातों का ध्यान रखेंगे और उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे। हालांकि भारत ने अपने बयान में चीन का नाम नहीं लिया। भारत ने यह बयान दुनिया में मानवाधिकार स्थिति पर हो रही चर्चा के दौरान दिया। भारत ने पहली बार हांगकांग के मुद्दे पर बोला है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के आक्रामक रवैये और पिछले महीने गलवान घाटी में भारत-चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत का यह बयान आया है। दोनों देशों के पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से लद्दाख में तनाव चल रहा है। देखा जाए तो चीनी दमन के खिलाफ व लोकतंत्र की मांग को लेकर हांगकांग में समय-समय पर जिस तरह से बड़े प्रदर्शन होते रहे हैं, वे चीन के लिए मुश्किल पैदा करने वाले रहे हैं। हांगकांग में पिछले साल छह महीने से ज्यादा समय तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमे थे, संसद का घेराव किया था और चीनी प्रतिष्ठानों पर हमले किए थे। हांगकांग के नागरिकों का यह जज्बा इस बात का प्रमाण है कि वे चीन के सामने झुकने वाले नहीं हैं। दुनियाभर के विरोध को दरकिनार करते हुए चीन ने आखिरकार हठधर्मिता और ताकत के साथ हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर दिया।

जाहिर है, अब इस कानून को आड़ में चीन हांगकांग के नागरिकों का दमन और तेज करेगा और लोकतंत्र समर्थकों को सबक सिखाएगा। चीन की संसद ने मई के आखिरी हफ्ते में इस कानून को पास कर दिया था। उसके बाद तीस जून को चीन के शीर्ष विधायी निकाय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमिटी ने भी हरी झंडी दे दी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि यह संकेत तो पहले ही मिल चुके थे कि चीन किसी भी सूत्र में हांगकांग को छोड़ने वाला नहीं है और वह हर हाल में इस कानून को लागू करके रहेगा। चीन अब तक जिस तरह से ताइवान, शिंजियांग और तिब्बत में आजादी की मांग करने वालों को कुचलता आया है, वही हांगकांग में होगा। क्या तानाशाही प्रकृति वाला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करके चीन अपने उस भरोसे को पूरा कर रहा है?

इस आवश्यकता को बहुत दृढ़ता के साथ रेखांकित किया जा चुका है कि सड़कों पर पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों को बिजली से चलने वाले वाहनों से विस्थापित किया जाना चाहिए। यह न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि यदि ऐसा संभव हो सके तो पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद में खर्च होने वाला देश का बहुत सारा धन भी बचाया जा सकता है। एक बार फिर सड़क परिवहन मंत्रालय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसकी पूरी संभावना है कि वह 'इलेक्ट्रिक व्हीकल्स' यानी बिजली से चार्ज होकर चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने की अपनी योजना को ठोस रूप देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। भारत ही नहीं दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागृति आई है और उन वाहनों को बेहतर विकल्प माना जा रहा है जिनकी बैटरी को बिजली से चार्ज करके आसानी से चलाया जा सकता है।

चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने तो ऐसे वाहनों की खरीद पर आर्थिक प्रोत्साहन (सब्सिडी आदि) देना भी प्रारंभ कर दिया है। भारत में भी कुछ कार उत्पादकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। बिजली से चलने वाले वाहन चूँकि भविष्य की जरूरत हैं और इस क्षेत्र में व्यापार की नई संभावनाएं छिपी हैं, इसलिए कुछ बड़ी कंपनियों ने तो इस दिशा में शोध, प्रयोग और अनुसंधान हेतु अच्छे खासा निवेश भी कर दिया है। उधर, भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने कुछ दिन पहले ही एक अप्रैल 2020 के बाद डीजल गाड़ियों का उत्पादन शनैः शनैः बंद कर देने का एलान कर दिया था। यह वह चोरिख है जब वाहनों के लिए बीएस-6 मानक अस्तित्व में आ जाएगा। तब मानकों के अनुसार डीजल इंजन बनाना ढेड़ लाख रुपए तक महंगा हो जाएगा।

दरअसल, पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल से चलने वाले वाहन पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया भर में सबसे प्रदूषित वायु वाले 15 शीर्ष शहरों में से 10 शहर भारत के हैं। इसने भी नीति-निर्माताओं को इस बात के लिए विवश किया कि वे हवा में वाहनों के कारण फैलने वाले प्रदूषण के समाधान के बारे में सोचें। लेकिन शहरों के विस्तार के कारण सभी वाहनों पर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बेशक सार्वजनिक परिवहन एक समुचित समाधान हो सकता है, लेकिन नागरिकों को निजी वाहनों के उपयोग से पूर्णतः वंचित कर देना किसी भी दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं कहा जा सकेगा। ऐसे में



बिजली से चलने वाले तंत्र के विकास के बाद कारें काफी महंगी हो जाएंगी और यह बढ़ी हुई कीमत आम ग्राहक को आकर्षित नहीं कर सकेगी। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए 'क्रेडिट प्वाइंट' जैसी सुविधा में कुछ खास किस्म की छूट का प्रावधान कर सकती है। चीन, अमेरिका या यूरोपीय संघ की तरह इन वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का विचार भी अपनाया जाना चाहिए।

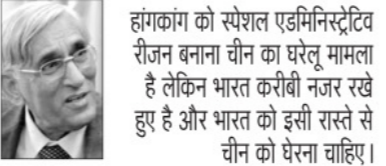
बिजली से चलने वाले वाहन श्रेष्ठ विकल्प हो सकते हैं। भारत की योजना यह है कि सन 2030 तक सड़कों पर मौजूद वाहनों में से तीस प्रतिशत वाहन बिजली से चलने वाले हों। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है। बिजली से चलने वाले तंत्र के विकास के बाद कारें काफी महंगी हो जाएंगी और यह बढ़ी हुई कीमत आम ग्राहक को आकर्षित नहीं कर सकेगी। भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए 'क्रेडिट प्वाइंट' जैसी सुविधा या टोल टैक्स आदि में कुछ खास किस्म की छूट का प्रावधान कर सकती है। चीन, अमेरिका या यूरोपीय संघ के सदस्यों की तरह इन वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का विचार फिलहाल सरकार का नहीं है। यों बीएस-6 मानक लागू होने के बाद डीजल कारों की कीमत में प्रत्याशित वृद्धि भी बिजली से चलने वाली कारों को प्रोत्साहित कर सकती है। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि कुछ साल पहले तक भारत में

डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बहुत अंतर रहा करता था। पेट्रोल की तुलना में डीजल बहुत सस्ता हुआ करता था। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन बिजली से चलने वाले वाहनों की खरीद के बाद ही उपभोक्ता वाहन के अपरिमित उपयोग के प्रति निश्चित नहीं हो सकेगा। बिजली से चलने वाली कारों में जिस लीथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, उस बैटरी को एक बार पूरी तरह चार्ज करने के बाद सामान्य परिस्थितियों में कार को दो सौ से तीन सौ किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। सामान्यतः शहरों में 30 से लेकर 40 किलोमीटर तक गाड़ी प्रतिदिन चलती है। ऐसे में यह स्थिति पहली नजर में तो आदर्श प्रतीत होती है कि एक बार गाड़ी को चार्ज करने के बाद उसे अपरिमित मजिल तक ले जाया जाए। लेकिन एक बार बैटरी खत्म होने के बाद उसे पूरी तरह चार्ज करने के लिए पूरी रात चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार द्रुत गति से चार्ज करने वाले चार्जिंग

स्टेशनों पर बैटरी 20 से 25 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो सकती है। लेकिन यदि बार-बार यह फास्ट चार्जिंग की गई तो इससे बैटरी पर बुरा असर पड़ेगा और वह अपेक्षाकृत कम समय तक ही चल पाएगी। उधर, पेट्रोल या डीजल खत्म होने पर किसी भी नजदीकी पेट्रोल-डीजल स्टेशन पर, जिनकी संख्या बहुत है, मनमाफिक ईंधन तक भरोसा जा सकता है। लेकिन देश में अभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बहुत कम है और ऐसे में यदि बिजली से चलने वाली कार से किसी परिवार को लंबी यात्रा करनी पड़े तो उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चार्जिंग में लगने वाले समय से बचने के लिए एक उपाय यह भी हो सकता है कि ऐसे विश्वसनीय स्टेशन विकसित किए जाएं जो डिस्चार्ज बैटरी के बदले चार्ज की हुई बैटरी उपलब्ध करा सकें। हालांकि कुछ कंपनियों ने इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन भारत में शहरों की दूरियां, सड़कों की हालत और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोगों की आतुरता की प्रवृत्ति को देखते हुए इस दिशा में बहुत काम करना शेष प्रतीत होता है। विकसित देशों में सामान्यतः एक बैटरी एक लाख 60 हजार किलोमीटर या फिर आठ वर्ष तक काम करती है। भारत में ये बैटरियां उपभोक्ताओं का कितना साथ निभा सकेंगी, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद बेकार हुई बैटरियों से निबटना भी समूची व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती होगा।

प्लास्टिक कचरे से निबट रही दुनिया के सामने बेकार बैटरियों का ढेर लग जाएगा। चीन और यूरोपीय संघ में तो कानून बना कर इन बैटरियों के समुचित व्यवस्थापन के लिए कार मालिकों को ही जिम्मेदार बनाया गया है और चीन में तो कुछ लोगों ने कार की बैटरियों को घरेलू उपयोग में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम भी किए हैं। यदि बिजली से चलने वाली कारें बड़ी संख्या में भारत की सड़कों पर आईं तो बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी आवश्यक होगी और कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो इस स्थिति को संभाल कर पाना बहुत दुरुह लगता है। बेशक जिन लोगों के घरों में गैरज है या जो अपने घर के भीतर कार खड़ी करते हैं, वो रात भर में बैटरी सहजता से चार्ज कर सकेंगे, लेकिन जो लोग अपने घर के बाहर गली में वाहन खड़ा करते हैं या अपने घर से दूर कार खड़ी करते हैं, उनके लिए वाहन की बैटरी को नियमित रूप से चार्ज करना बड़ी परेशानी का कारण बनेगा।

दिव्य

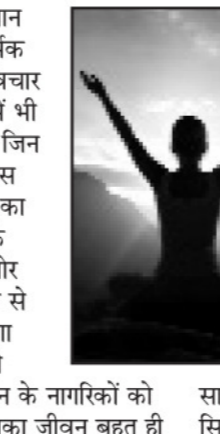


हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया चीन का घरेलू मामला है लेकिन भारत करीबी नजर रखे हुए है और भारत को इसी रास्ते से चीन को घेरना चाहिए।

पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ

सत्यार्थ

जिन दिनों भारत में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध धार्मिक सुधार को लेकर अपने नए विचार रख रहे थे, उन्हीं दिनों चीन में भी एक सुधारक का जन्म हुआ, जिन का नाम कन्फ्यूशियस था। उस समय चीन में झोऊ राजवंश का शासन चल रहा था। समय के साथ झोऊ राजवंश के कमजोर पड़ने के कारण चीन में बहुत से राज्य कायम हो गए, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ऐसे समय में कन्फ्यूशियस ने चीन के नागरिकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। उनका जीवन बहुत ही



सामने रखा-ईश्वर, राज्य और जनता का सिद्धांत, जिसके सामने सब झुक गए। उन्होंने

नैतिकता का पाठ

साधारण था। कन्फ्यूशियस पशुओं को घास डालते हुए जब जीवन के गहन सिद्धांतों पर सोचते रहते, तो किसी को उन पर यकीन नहीं होता था कि यह शख्स एक दिन उनका जीवन बदल देगा। 27 साल तक मजदूरी करने के बाद जब उन्होंने आठ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो भी यह फिजूल ही नजर आया। 37 साल की उम्र में उन्होंने चीन की परंपरागत किताबों को खंगलने के बाद एक सिद्धांत सामने रखा-ईश्वर, राज्य और जनता का सिद्धांत, जिसके सामने सब झुक गए। उन्होंने

में सत्याभास को सत्य से, जो को गेहूं से, मीठी दुनिया को अच्छाई से और कड़वे वचन को इमानदारी से अलग मानता हूँ, तभी सही न्याय कर पाता हूँ। ऐसी मान्यता है कि एक विचारक बिलकुल अलग तरह की जिंदगी जीता है, जबकि कन्फ्यूशियस ने इसी चीज को बदला। जब उनसे पशुओं को चारा देने को कहा जाता था, तो वे उस में अपने तरीके से दर्शन ढूँढ लेते। देर रात घर को लौटने पर जब उनके सामने से खाने की प्लेट हटा ली जाती, तो वे उसमें भी दूसरों के हक की बात सोच लेते थे। सचमुच महान व्यक्ति छोटी चीजों में भी बड़ी चीजें खोज लेता है।

श्रीलंका में हो सकता है आईपीएल

यूएई भी रेस में, बोर्ड को वर्ल्ड कप पर फैसले का इंतजार



नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन यूएई या श्रीलंका में करवाए जाने की सभी संभावनाओं को देखा जा रहा है। इस पर आखिरी घोषणा करने से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप के भविष्य पर फैसले का इंतजार कर रहा है। इस वर्ल्ड का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित था। मामले को करीब से जानने वाले बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि विचार तो लीग को भारत

में ही खेलने का था लेकिन कोरोना वायरस महामारी के हालात तो देखते हुए बोर्ड आखिरकार इस टूर्नामेंट को यूएई या श्रीलंका में आयोजित करवा सकता है। अधिकारी ने कहा, हमने अभी यह तय नहीं किया है कि टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इस साल यह विदेश में होगा। भारत में ऐसे हालात लग नहीं रहे कि जहाँ एक या दो स्थानों पर मैच करवाए जाएं और फिर ऐसा माहौल तैयार किया जाए जो खिलाड़ियों और आम

जनता के लिए सुरक्षित हों हालांकि मैच खाली स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। अधिकारी ने कहा, इस दौड़ में यूएई और श्रीलंका सबसे आगे हैं। अब लीग का आयोजन कहाँ करवाना है यह कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए किया जाएगा। लाजिस्टिक को भी ध्यान में रखना होगा ऐसे में हमें जल्दी फैसला करना होगा।



वेनई के कैम्प में धोनी पूरी फॉर्म में दिख रहे थे : पीयूष चावला

वेनई सापुर क्रिस के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जब कैम्प में आए थे तब वह लय से बाहर नहीं लग रहे थे। यह कहना है टीम के लेग स्पिनर पीयूष चावला का। धोनी आईपीएल-13 के साथ वापसी करने वाले थे लेकिन कोरोनावायरस के कारण इसमें देरी हो गई। वेनई ने लीग की शुरुआत से पहले ही चेपक में अपना कैम्प लगाया था जिसमें धोनी ने हिस्सा लिया था लेकिन कोविड-19 के कारण कैम्प को बीच में ही समाप्त कर दिया गया था। चावला ने आकाश चोपड़ा के यूट्यूब शो पर बात करते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो जब क्रिकेटर लंबे ब्रेक के बाद वापसी करता है तो लोगों को लगता है कि वह थोड़ा लय से बाहर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वह राती में जरूर कुछ न कुछ कर रहे थे क्योंकि जब धोनी वेनई के कैम्प में आए तो वह लय से बाहर नहीं दिखे। उनका रूटीन था कि वह चार-पांच गेंद खेलेंगे और फिर बड़े शॉट मारते थे। उन्होंने कहा, वह दर तक बल्लेबाजी करते थे। सुरेश रैना, अंबाती रायडू, धोनी और मुरली विजय कैम्प में सीमित खिलाड़ी थे और गेंदबाज ज्यादा थे इसलिए हर कोई दो-दोई घंटे बल्लेबाजी करता था।

विंडीज के महान बल्लेबाज एवर्टन वीक्स का निधन

थी-डब्ल्यू की अंतिम कड़ी वीक्स ने 95 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस



बारबाडोस। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर एवर्टन वीक्स का लंबी बीमारी के बाद 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। महान थी-डब्ल्यू की अंतिम कड़ी वीक्स का निधन बारबाडोस में उनके निवास पर हुआ। वीक्स को पिछले वर्ष जून में दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद से उनकी तबीयत खराब चल रही थी।

वीक्स ने अपने क्रिकेट करियर में 48 टेस्ट मैच खेले थे और 4455 रन बनाए थे। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 58.62 रहा। उन्होंने कुल 15 शतक बनाए थे। वीक्स के निधन के बाद विश्व क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और इस खेले से जुड़े विशिष्टताओं और लोगों ने शोक व्यक्त किया है। फ्रैंक वरिल और क्लाड वॉलकोट के साथ वीक्स वेस्टइंडीज के प्रसिद्ध थी डब्ल्यू में शामिल थे। ये तीनों खिलाड़ी

इंग्लैंड के खिलाफ की थी करियर की शुरुआत

वीक्स ने 1947-48 में इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट में अपनी पारी की शुरुआत की थी। वह उस मैच में कुछ कमाल नहीं कर पाये थे लेकिन इसके बाद जल्द ही उन्होंने लगातार पांच शतक जड़े थे जिनमें से इंग्लैंड के खिलाफ एक और भारत के खिलाफ चार शतक थे। वीक्स ने क्रिकेट और फुटबॉल पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए 14 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया था। वह बारबाडोस रजिमेंट का हिस्सा थे और उन्होंने फरवरी 1945 में त्रिनिदाद और टोबैगो के खिलाफ बारबाडोस के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला था। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 55.34 के औसत से 12010 रन बनाये थे। वीक्स ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कमेंटरी के रूप में काम किया और युवा खिलाड़ियों के आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1994 में भारत-श्रीलंका की तीन वनडे मैचों की सीरीज में मैच रेफरी बने थे। उन्हें 1995 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी।

ग्रेग चैपल भारतीय नहीं, उन्हें टारगेट करना आसान: पटान

नई दिल्ली। इरफान पटान के पास रफतार थी। वह गेंद को रिविंग कर सकते थे। बल्ले से भी उपयोगी पारियां खेल सकते थे। उन्हें भविष्य का कपिल देव तक कहा जाने लगा था।



गेंद और बल्ले दोनों से वह कमाल दिखा सकते थे। लेकिन इरफान उन उंचाइयों को नहीं छू पाए जिनकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। इसके पीछे कई लोगों को कई वजह दिखाईं। सबसे सामान्य नजरिया यह था कि तब के कोच ग्रेग चैपल ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। हालांकि अब इरफान ने इस पर अपनी राय रखी है। पटान ने कहा कि पूर्व भारतीय कोच चैपल पर उनका करियर बर्बाद करने का आरोप लगाना सही नहीं है। उन्होंने कहा, यह सच नहीं है कि ग्रेग चैपल ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। अब चूँकि वह

भारतीय नहीं हैं इसलिए उन पर सारा दोष मढ़ना आसान हो जाता है। इरफान ने चैपल के बारे में यह भी कहा कि उन्हें गलत समझा गया। चैपल की आलोचना इसलिए भी की जाती है क्योंकि कहा जाता है उन्होंने पटान को नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। कई लोग मानते हैं कि यह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का ही आईडिया था। हालांकि पटान ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह सचिन तेंडुलकर का आईडिया था।

मनोहर ने बीसीसीआई का नुकसान किया है : शाह

नई दिल्ली। बीसीसीआई के पूर्व सचिव निरंजन शाह ने कहा है कि शशांक मनोहर का आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना जाहिर सी बात थी और अब उन्हें पलट कर देखना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। शाह ने कहा कि शशांक मनोहर का आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना जाहिर सी बात है। शशांक को इस बात को लेकर मिलेजुले भाव आ रहे होंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वे क्या कर सकते थे और उनके कार्यकाल में भारत में क्रिकेट के साथ क्या किया गया। उन्होंने कहा, अब वह आराम के दौर में होंगे और इस दौरान उन्हें बतौर आईसीसी चेयरमैन अपने कार्यकाल की समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल के दौरान बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट का किनासा नुकसान हुआ है। शाह ने आगे कहा, बीते कुछ वर्षों में बीसीसीआई ने काफी कुछ झेला है। आईसीसी ने इस दौरान भारत में क्रिकेट और बीसीसीआई को हुए नुकसान का फायदा उठाया है।

एशिया कप में बेहतर प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त थी : सुमन

इंफाल। जूनियर भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सुमन देवी थोडम ने कहा है कि जूनियर महिला टीम जापान में होने वाले 2020 जूनियर एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर आश्वस्त थी लेकिन देश में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लगाये गये लॉकडाउन के कारण इसकी तैयारी फिलहाल थम गई। 2020 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप की शुरुआत इस वर्ष जापान में छह अप्रैल से होना था

लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इस टूर्नामेंट को स्थगित करना पड़ा। सुमन ने कहा, हम मार्च के पहले सप्ताह से नेशनल कोचिंग कैंप में थे और हम जूनियर एशिया कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे थे क्योंकि एशिया कप में अच्छा खेलने का लाभ हमें दक्षिण अफ्रीका में होने वाले एफआईएफ जूनियर विश्व कप 2021 में मिलता। सुमन ने पिछले वर्ष चार देशों के कैंटर

फिट्जेराल्ड अंडर-21 टूर्नामेंट और बेलायूस टूर में भारतीय महिला टीम का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में हुये तीन देशों के टूर्नामेंट में टीम के बेहतरीन प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुमन ने कहा, हमने पिछले वर्ष कुछ अच्छे प्रदर्शनों से एक बेहतरीन टीम बने और हम जापान में होने वाले जूनियर एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर आश्वस्त



थे। सुमन ने लॉकडाउन के दौरान बेंगलुरु के नेशनल कोचिंग कैंप में ही रूकने का फैसला किया जबकि उनके साथ की कई खिलाड़ी उस वक्त अपने घर रवाना हो गयी थीं।

फिडे के अध्यक्ष आकाडी डवोरकोविच का कहना विश्व शतरंज चैम्पियनशिप 2021 तक हो सकती है स्थगित

मास्को। विश्व शतरंज चैम्पियनशिप अगले साल तक के लिए स्थगित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अध्यक्ष आकाडी डवोरकोविच ने इस बात की जानकारी दी। चैम्पियनशिप इसी साल दिसंबर में दुबई में होनी थी लेकिन डवोरकोविच का कहना है कि महासंघ अब 2021 में इसे कराने पर विचार कर रही है। अध्यक्ष हवाले से कहा गया कि विश्व चैम्पियनशिप के मैच मौजूदा स्थिति को देखते हुए निश्चित तौर पर अगले साल तक के लिए स्थगित हो सकते हैं। हमने अनाधिकारिक तौर पर इस पर बात की है। मुझे लगता है कि औपचारिक प्लान जल्दी हो सकता है। हम कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। 2021 के बसंत और पतझड़ पर लेकिन हम हर चीज की घोषणा बाद



में करेंगे। डवोरकोविच ने कहा कि फिडे अपना पहला ऑनलाइन शतरंज ओलम्पियाड आयोजित करेगी। उन्होंने कहा, इस साल ओलम्पियाड खातीं मैनेजर और मास्को में होना था, लेकिन हमने इसे अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया है। इस साल हम एक ऑनलाइन ओलम्पियाड आयोजित करेंगे और दो-तीन दिन में राष्ट्रीय टीमों के पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा टीमों हिस्सा लें। हमारे 195 सदस्य हैं। मैं नहीं जानता की सभी इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं। मैं नहीं जानता की सभी इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं।

शेफील्ड शील्ड में उपयोग होगी कुकाबुरा गेंद

सिडनी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया है कि वह इस बार ग्रीष्मकाल में शेफील्ड शील्ड में ड्यूक गेंद का इस्तेमाल नहीं करेगी और कुकाबुरा गेंद का उपयोग करेगी। इसे स्पिनरों को वापस मैच में प्रभावी बनाने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सीजन 2016-17 से ही क्रिसमस के बाद होने वाले मैचों में ड्यूक गेंद का इस्तेमाल होता था ताकि गेंदबाज इंग्लैंड की परिस्थितियों में खेलने की तैयारी कर सकें, जहां ड्यूक गेंद का इस्तेमाल होता है। परन्तु क्रिकेट में हालांकि कुछ लोगों की शिकायत थी कि ड्यूक गेंद तेज गेंदबाजों को मदद करती है और इससे स्पिनरों को नुकसान होता है।

इंग्लैंड के मैच में दिखा जश्न मजाने का नया तरीका

कोरोनावायरस के कारण हुआ बदलाव

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के कारण क्रिकेट में कुछ बदलाव हुए हैं और इसी बीमारी के डर से विकेट लेने के बाद जश्न मजाने के तरीके पर भी अंतर पड़ेगा। यह नया तरीका क्या हो सकता है इसकी बगनी इंग्लैंड टीम के आपसी अभ्यास मैच में देखने को मिली जहां खिलाड़ी हाथ मिलाने, हाई फाइव के बजाए कोहनी टकराते हुए विकेट का जश्न मजाने देखे गए। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड इसीबीबी ने हाल ही में एक वीडियो टवीट किया है जिसमें तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, जो ए डेनले का विकेट लेने के बाद बाकी खिलाड़ियों से कोहनी टकरा कर जश्न मना रहे हैं। इस दौरान हालांकि कुछ हाइव फाइव भी देखे गए लेकिन उनकी संख्या कम थी। ज्यादातर खिलाड़ी कोहनी मिलकर कर ही जश्न मना रहे थे। यह अभ्यास मैच



वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली टीम मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए है। इस सीरीज में भी संभवतः इंग्लैंड की तरह से इसी तरह विकेट का जश्न मजाने हुए देखा जा सकता है। इंग्लैंड का यह आपसी अभ्यास मैच बेन स्टोक्स एकादश और जोस बटलर एकादश के बीच खेला जा रहा है।

ओडिशा के स्टील प्लांट में धमाका

कर्मचारियों पर गिरा गर्म पिघला लोहा, 7 झुलसे

राउरकेला, (एजेंसी)। ओडिशा के झारसुगुडा में टीपीएसएल फैक्ट्री में गुरुवार तेज ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में सात लोग झुलस गए हैं। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह लीकज होना बताया जा रहा है। सभी घायलों का इलाज राउरकेला के अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। झारसुगुडा जिले के धुरहादिही पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लहाडाबुडा में गुरुवार सुबह साढ़े नौ बजे यह घटना हुई। ठाकुर प्रसाद शामिल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से राउरकेला भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि चूँकि डीएचएच की कोई बर्न यूनिट नहीं है इसलिए घायलों को राउरकेला इस्पताल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, उन्होंने झारसुगुडा के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ) जगदीश चंद बारिक को सूचना भेज दी है। दो कर्मचारियों की हालत गंभीर है।



दूसरी मंजिल पर हुआ ब्लास्ट ब्लास्ट प्लांट की दूसरी मंजिल पर हुआ। यहां पर फर्नेस में लीकज से तेज आवाज के साथ यह फटा। भट्टी से गर्म तरल लोहा सात कर्मचारियों पर आकर गिरा। जिससे वे जल गए।

ये कर्मचारी हुए घायल घायल व्यक्तियों में शंकर (40), आनंद साहू (45), गणेश स्वैन (30), रणजीत सिंह (32), सुमंत माझी (24) और सहदेव पटेल (30) शामिल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से राउरकेला भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि चूँकि डीएचएच की कोई बर्न यूनिट नहीं है इसलिए घायलों को राउरकेला इस्पताल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, उन्होंने झारसुगुडा के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ) जगदीश चंद बारिक को सूचना भेज दी है। दो कर्मचारियों की हालत गंभीर है।

कोच सिमंस को मिला विंडीज क्रिकेट बोर्ड का समर्थन

बारबाडोस। अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण आलोचना झेल रहे वेस्ट इंडीज के मुख्य कोच फिल सिमंस को अपने क्रिकेट बोर्ड का समर्थन मिला है। बारबाडोस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कोडे रिले ने कोरोना महामारी के बीच अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल वाले सिमंस को कोच पद से तत्काल हटाने की मांग की थी। सिमंस ने इंग्लैंड के खिलाफ आठ जुलाई से शुरू हो रही तीन टेस्ट-मैचों की सीरीज से पहले अपने ससुर की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति ली थी। रिले ने अंत्येष्टि में शामिल होने के सिमंस के निर्णय को गैरजिम्मेदाराना और लापरवाही बरा बताया था और कहा था कि ऐसा कर उन्होंने टीम के सदस्यों का जीवन खतरों में डाला है। रिले क्रिकेट वेस्टइंडीज के बोर्ड के सदस्य भी हैं। सिमंस को पिछले सप्ताह अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वेस्टइंडीज प्रशिक्षण शिविर को छोड़ने की अनुमति दी गयी थी।

श्रीनिवासन से लड़ने वाले आदित्य अब श्री के पक्ष में

श्रीनिवासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे

पटना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अदालत तक लड़ाई लड़ने वाले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा अब श्रीनिवासन के पक्ष में आ गए हैं। आदित्य ने कहा, पिछले पांच वर्षों में केवल एक शख्स के कारण बीसीसीआई को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और यह शख्स शशांक मनोहर हैं जो बीच समंदर

में जहाज को डूबता छोड़ कर खुद निकल जाते हैं चाहे वह बीसीसीआई हो या आईसीसी। वर्तमान परिस्थिति में बीसीसीआई की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि बीसीसीआई में अध्यक्ष सौरभ गांगुली अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह से निर्वाह करें तथा आईसीसी में बीसीसीआई की ओर से चेयरमैन के रूप में श्रीनिवासन को एक बार फिर भेजने की पहल की जाए और यही समय का भी वह चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। कई बार वह ऐसे फैसले लेते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता लेकिन बाद में आपको हैरानी होती है कि आखिर कैसे यह टीम के लिए पक्ष में गया।

मैं चाहता हूँ धोनी अगले 10 साल तक खेलें : हसी

धोनी और फ्लेमिंग के बीच मजबूत संबंधों की तारीफ की

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मध्यक्रम बल्लेबाज माइकल हसी ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि धोनी अगले 10 साल और क्रिकेट खेलना जारी रखें। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी ने धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग के बीच मजबूत संबंधों की भी तारीफ की। 'माइकल हसी ने क्रिकेट से जुड़े कई पहलुओं पर अपनी राय जाहिर की। इसमें चेन्नई सुपर

किंग्स के अलावा इस साल के अंत में प्रस्तावित भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज भी शामिल थी। धोनी और फ्लेमिंग के बीच रिश्तों पर उन्होंने कहा कि दोनों एक-दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। हसी ने कहा, वे दोनों एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते हैं। उन दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। और दोनों को खेल की गहरी समझ है। दोनों बहुत स्पोर्ट्स हैं और साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं। मिस्टर क्रिकेट के नाम से मशहूर हसी ने

धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि वह हमेशा अपने खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही टीम के भले के लिए कई बार अचानक हैरान करने वाले फैसले कर लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच हसी ने कहा, कप्तान के तौर पर मुझे महेंद्र सिंह धोनी बहुत पसंद है। वह अपने खिलाड़ियों को काफी सर्पोट करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। बेशक, मैदान में तकनीकी पक्ष का भी वह चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। कई बार वह ऐसे फैसले लेते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता लेकिन बाद में आपको हैरानी होती है कि आखिर कैसे यह टीम के लिए पक्ष में गया।



ट्विटर ने राष्ट्रपति ट्रंप की पोस्ट से तस्वीर हटाई

वाशिंगटन, (एजेंसी)। ट्विटर ने कॉपीराइट उल्लंघन का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से एक तस्वीर हटा दी है। श्री ट्रंप ने 30 जून को एक ट्वीट किया था, जिस पर अब एक नोटिस दिख रहा है, 'कॉपीराइट धारक की एक रिपोर्ट के जवाब में' तस्वीर को हटा दिया गया है। एक्सओएस वेबसाइट के मुताबिक श्री ट्रंप के ट्वीट में जिस तस्वीर पर यह सवाल खड़ा हुआ है वह वर्ष 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटोग्राफर डैमियन विटर ने खींची थी। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने इस तस्वीर को हटाये जाने अनुरोध की पुष्टि की है क्योंकि ट्रम्प ने अखबार की बिना अनुमति के तस्वीर साझा की थी। पिछले कुछ हफ्तों में श्री ट्रम्प के अकाउंट से कॉपीराइट उल्लंघन का सोशल मीडिया पर यह दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले जून के अंत में फेसबुक और ट्विटर ने ट्रम्प के एक पोस्ट पर सजा निलया था।

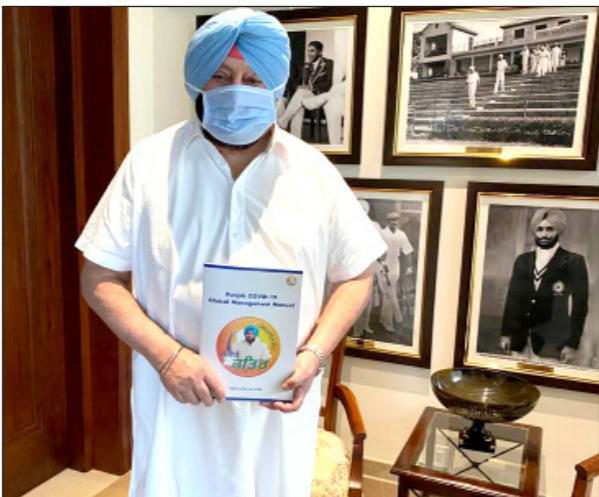
मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड के इलाज के प्रबंधन संबंधी पुस्तिका जारी

आसान समझी जाने वाली पुस्तिका 'मिशन फतेह' के लिए और कारगर सिद्ध होगी

चंडीगढ़/ब्यूरो

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 'पंजाब कोविड -19 इलाज प्रबंधन पुस्तिका' जारी की है। एक ही हवाले से आसानी से समझे जाने वाली इस पुस्तिका का उद्देश्य महामारी के हर पहलू से निपटने के लिए तालमेल वाली पहुँच के द्वारा मृत्यु दर को घटाना है।

मुख्यमंत्री ने पुस्तिका को उनकी सरकार के 'मिशन फतेह' के लिए और कारगर सिद्ध होने का जिक्र करते हुये कहा कि यह पुस्तिका कोविड प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और राज्य की जरूरतों के दृष्टिकोण से तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तिका कोरोनावायरस के साथ पॉजिटिव मरीजों को देखभाल में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को महामारी के साथ बेहतर ढंग से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों की पहुँच मुहैया करवाएगा।



पी.जी.आई. के पूर्व डायरेक्टर डा. के.के. तलवाड़ के नेतृत्व में माहिर कमेटी की तरफ से तैयार की पुस्तिका में कोविड के पॉजिटिव मरीजों के इलाज प्रबंधन पर आधारित ऑडियो-वीडियो साधनों को समझने, कलर कोडिंग का मूल्यांकन यंत्र और व्यावहारिक

तजुर्बों के आधार पर हवाला मापदण्डों को शामिल किया गया है। डी.एम.सी. लुधियाना के दिल के रोगों के जाने-माने माहिर डा. बिशव मोहन की तरफ से बुलायी गई कमेटी विश्व भर की मशहूर संस्थाओं के कई नामवर स्वास्थ्य माहिरों पर आधारित है।

यह पुस्तिका मामूली और साधारण रूप से गंभीर कोविड मामलों को इलाज जरूरतों को पूरा करने में सहायता करेगी। मामूली मामलों के लिए इस पुस्तिका में घरों में एकांतवास मरीजों की प्रगति का जायजा लेने के लिए स्व-मूल्यांकन प्रश्नावली और घर-आधारित टैस्टों को शामिल किया गया है।

इसमें हर जिले में समर्पित माहिरों की ताजा सूची शामिल है जिससे कोविड मामलों से निपटने में जिला मैडीकल टीम जिनको माहिर की निगरानी की जरूरत होती है, को सहायता मिलेगी जिससे जितना संभव हो सके, मृत्यु दर घटाई जा सके। इसी तरह पुस्तिका कोविड -19 के मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के मामलों को भी दर्शाती है और यह प्रबंधन प्रोटोकॉल के हिस्से के तौर पर मानसिक रोगों के माहिरों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक वर्कर्स का साइटा प्लेटफॉर्म दर्शाता है।

कमिशनरेट पुलिस और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से दो व्यक्ति 3000 ट्रामाडोल गोलियों के साथ गिरफ्तार

जालंधर/नीरज

पुलिस कमिशनरेट और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से संयुक्त कार्यवाही के दौरान बस्ती बावा खेल से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके 3000 ट्रामाडोल गोलियाँ जब्त की गईं।

दोनों दोषियों की पहचान जय प्रकाश गली नंबर 4 और अजय कुमार बस्ती बावा खेल के राज नगर के तौर पर हुई है।

इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए पुलिस कमिशनर जालंधर श्री गुर्प्रीत सिंह भुखर ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस कमिशनरेट की टीम जिस का नेतृत्व इंस्पेक्टर जगदेव सिंह, सहायक सब इंस्पेक्टर मुकेश और सिपाही जसप्रीत और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम जिस में सहायक डायरेक्टर सन्दीप कुमार यादव, इंटेलिजेंस अफसर जे.पी.सिंह, विकास सिंह, सुजीत कुमार शामिल थे ने बस्ती बावा खेल में दोषियों को काबू करके इन से ट्रामाडोल की गोलियाँ जब्त की गईं। उन्होंने बताया कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एन.डी.पी.एस.एकट की धारा 8,22,25,29 और 60 के अंतर्गत दोषियों जिला केस दर्ज किया गया है और जब्त गोलियों के स्रोतों बारे जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस कमिशनर ने जिले में नशों



की लानत को खत्म करने के लिए पुलिस कमिशनरेट की वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस धिनौने जुर्म में लिस व्यक्तियों के के जिला जौरो टोलरेंस नीति को अपनाया गया है और जब्त गोलियों के स्रोतों बारे जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस कमिशनर ने जिले में नशों

को कमिशनरेट पुलिस की तरफ से किसी भी कामत पर बक्शा नहीं जायेगा। श्री भुखर ने कहा कि पुलिस कमिशनरेट की तरफ से जहाँ नशों की सप्लाय और इस को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त चौकसी रखी जा रही है।

2 आई.ए.एस. और 1 पी.सी.एस. अधिकारी का तबादला

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब सरकार ने आज 2 आई.ए.एस. अधिकारियों और 1 पी.सी.एस. अधिकारी के तुरंत प्रभाव से तबादले/तैनाती के आदेश जारी किये हैं।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आई.ए.एस. अधिकारी श्री चन्द्र गैद को कमिशनर, पटियाला डिवीजन, पटियाला तैनात किया गया है और डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री घनश्याम थोरी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जंग -ए -आजादी यादगार फार्डेशन, जालंधर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरह पी.सी.एस. अधिकारी सचिव, पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड श्री अमनदीप बांसल को अतिरिक्त सचिव, मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

एंटी लारवा सैल ने सात स्थानों से डेंगू लारवा की पहचान की

जालंधर/नीरज

राज्य सरकार की तरफ से शुरू किये गए मिशन फतेह के अंतर्गत लोगों को पानी एकत्रित वाले स्थानों, कुलों और फाल्टू चीजों की साफ-सफाई और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में जागरूकता मुहिम चलाई गई। ऐंपीडीमोलोजिस्ट डा.सतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के लारवा विरोधी सैल की तरफ से शहर की अलग-अलग स्थानों से सात स्थानों पर डेंगू लारवा की पहचान की गई।

लारवा विरोधी सैल जिस में जसविन्दर सिंह, हरविन्दर सिंह, तरलोचन राम, सुमित, राज कुमार, डेविड ईसा मसीह, शेर सिंह और राम प्रकाश शामिल थे की तरफ से प.न.आई.टी.कबीर नगर, मास्टर महंगा सिंह कालोनी, रामा मंडी, गोल्डन ऐविन्यू और दूसरे स्थानों की जांच की गई।

लारवा विरोधी टीमों की तरफ से कबीर नगर में 6 और मास्टर महंगा सिंह कालोनी में एक जगह पर डेंगू लारवा पाया गया। जांच दौरान टीमों से तरफ से 159 घरों का दौरा करके 61 कुलों और 166 फाल्टू चीजों की जांच की गई।

इस अवसर पर डा.सतीश कुमार ने लोगों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इन स्थानों पर मच्छरों की तरफ से डेंगू लारवा पैदा किया जाता है जिससे डेंगू, मलेरिया आदि जैसी कई बीमारियाँ पैदा होती हैं। उन्होंने बताया कि इस जांच का मुख्य मंतव्य डेंगू लारवा के पैदा होने वाले स्थानों की पहचान करना है।

27 और मरीजों ने कोरोना वायरस खिलाफ जंग में फतेह हासिल की कोविड केयर सेंटर से मिली छुट्टी

पंजाब सरकार की तरफ से मानक इलाज के लिए धन्यवाद

जालंधर/नीरज

जिले को कोरोना वायरस मुक्त बनाने की तरफ एक ओर कदम बढ़ाते हुए आज कोविड केयर सेंटर से 27 और कोरोना वायरस मरीजों को इलाज उपरांत छुट्टी दी गई।

कोविड केयर सेंटर से छुट्टी मिलने वाले मरीजों में किरन कुमार, गोपाल, राहुल शर्मा, विकास राज, तारा सिंह, सुखजिन्दर सिंह, राना लाल, बलविन्दर सिंह, बलवीर सिंह, तनुजा खातिवान, सुमित, गुल्शन, सुनीता, विरोधी राम, धर्मदेव, मंगा राम, कुलदीप कौर, गुरजीत कुमार, राजा राम, काजल, सुनीता, रामेश लाल, अनुराग, आशा रानी, तरसेम लाल और जतिन शामिल थे जिनको कोविड -19 प्रभावित होने उपरांत कोविड केयर सेंटर में दखिल करवाया गया जहाँ सीनियर मैडीकल अधिकारी डा.जगदीश कुमार के नेतृत्व वाली टीम की तरफ से पूरी दृढ़ता के साथ इलाज किया गया।

छुट्टी मिलने उपरत इन सभी मरीजों की तरफ से कैप्टन अमरिन्दर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से कोविड -19 से प्रभावित मरीजों के लिए किये गए पुख्ता इंतजामों के लिए धन्यवाद किया गया। उनकी तरफ से इस मुश्किल घड़ी में डाक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य वर्करों की तरफ से उनके मानक इलाज को यकीनी बनाने की भी प्रशंसा की गई। इस अवसर पर डाक्टरों और पूरे स्टाफ को बधाई देते हुए सिविल सर्जन डा.गुरिन्दर कौर चावला ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस खिलाफ लड़ा जा रही जंग दौरान यह एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि मैडीकल माहिरों की वचनबद्धता और हरेक पंजाब निवासी खास कर जालंधर निवासियों की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोरोना वायरस खिलाफ जंग को जीत लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री घनश्याम थोरी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस खिलाफ जंग हर हाल में जीतने के लिए पाबंद है।

सुखजिन्दर सिंह रंधावा द्वारा अनुपम खेर को सम्बित पात्रा की प्रशंसा करने के लिए गुरु साहिब के शब्दों का हवाला देने के लिए सख्त आलोचना

अकाली नेता आखिर कब तक भाजपा के सिख और पंजाब विरोधी रवैये को सहन करते रहेंगे - रंधावा

चंडीगढ़/ब्यूरो

सीनियर कांग्रेसी नेता स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने भाजपा संसद मेंबर किरण खेर के पति और भाजपा की विचारधारा के कट्टर समर्थक अनुपम खेर की तरफ से दशमेश पिता श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के पावन शब्द भाजपा के प्रवक्ता सम्बित पात्रा के कसौदे पढ़ने के लिए बरतने की सख्त आलोचना की है।

फ़िल्म अभिनेता अनुपम खेर की तरफ से सिखों की धार्मिक संवेदनाओं को गहरी ठेस पहुँचाने के लिए की

इस धिनौनी हरकत के बावजूद भाजपा के साथ नाखुन-मांस का रिश्ता रखने वाली हिस्सेदार पार्टी की तरफ से चुपी साधने पर स. रंधावा ने अकालियों को आड़े हाथों लेते हुये कहा कि आखिर अकाली कब तक पंजाबियों और सिखों के निरादर करने वालों के सुर में सुर में मिलाते रहेंगे।

साल 2014 के संसदीय मतदान में समकालीन अकाली मंत्री विक्रम मजीठिया की तरफ से अमृतसर से उस समय पर के भाजपा उम्मीदवार अरुण जेतली के कसौदे पढ़ते हुये

केंद्रीय वजीरी की खातिर बादल परिवार ने भाजपा के पास सभी हित गिरवी रखे

वाणी का निरादर किये जाने की घटना याद करते हुये स. रंधावा ने कहा कि जो कथित पंथक पार्टी का नेता खुद ऐसा गुनाह कर सकता है तो उसके हिस्सेदार से क्या उम्मीद की जा सकती है ?

कांग्रेसी मंत्री ने कहा कि श्री खेर ने सोची समझी साजिश के अंतर्गत सिखों के ज़ब्तारों पर चोट पहुँचाने की घटिया हरकत की है

जिसको सिख कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे शर्मनाक बात यह है कि खेर की पत्नी किरण खेर संसद में पंजाब की राजधानी की नुमायंदगी करती है। फिर भी उसके पति ने सिखों के जन्मतों को झिंझोड़ने की हिमाकत की।

स. रंधावा ने अकालियों को घेरते हुये कहा कि यदि बादल परिवार

ने अकाली दल के नैतिक मूल्यों को ताक पर रख कर भाजपा की झोली में पड़ने का फ़ैसला कर ही लिया है तो बादल परिवार को अकाली दल के पद छोड़ कर भाजपा को ही माँ-पार्टी बना लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लगातार अल्पसंख्यकों, संघीय ढांचे और खास तौर पर किसानों को तबाह करने पर तुली हुई है परन्तु इस बात से हैरानी होती है कि भाजपा की तरफ से अपने फ़ैसले संबंधी स्पष्टीकरण देने से पहले ही सुखबीर बादल और केंद्रीय मंत्री

हरसिमरत बादल सोचे समझे बिना मोदी के प्रशंसा भरे शब्द गाने शुरू कर देते हैं।

कांग्रेसी नेता ने कहा कि अकाली दल आखिर कब तक केंद्रीय वजीरी के लालच में अपने राज्य, अपने राष्ट्र और अपने लोगों की भावनाओं के साथ होता खिलवाड़ बेझिझक स्वीकृत करता रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सिख लीडरशिप के साथ अकाली दल को भी अनुपम खेर की हिमाकत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुये समूची सिख जाँमेदार को घेरते हुये कहा कि

जिला प्रशासन ने सतलुज दरिया के किनारों को मजबूत करने के लिए मगनरेगा कामगारों को लगाया

जालंधर/ब्यूरो

जिला प्रशासन ने बरसात के मौसम से पहले जिले की तीन सब डिविजन फ्लैवर, नकोदर और शाहकोट में सतलुज दरिया के किनारों को मजबूत करने के लिए मगनरेगा कामगारों को लगाया गया है। डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री घनश्याम थोरी की हिदायतों पर उप मंडल मैजिस्ट्रेटों की तरफ से नियमित तौर पर नाजुक स्थानों का दौरा किया जा रहा है जबकि ड्रेनज विभाग के अधिकारियों की तरफ से पहले ही फील्ड में रह कर काम को जल्द पूरा होने को यकीनी बनाया जा रहा है।

इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री घनश्याम थोरी ने बताया कि दरिया सतलुज के नाजुक स्थानों पर मगनरेगा कामगारों को लगाया गया है जिससे बाढ़ सुरक्षा प्रबंधों को अच्छी तरह समय से पहले पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि मानरेगा कामगारों की तरफ से ड्रेनज विभाग के इंजीनियरों की देख रेख में काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ड्रेनज और पंचायत विभाग के अधिकारियों की सांझी टीमों की तरफ से संवेदनशील स्थानों पर दिन-रात काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ती है तो इस काम में और साधन लगाने के लिए फंड को कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सतलुज दरिया के संवेदनशील स्थानों को हर कामत पर मजबूत करने को प्राथमिकता दी जा रही है जिससे लोगों को जान-माल की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके।

उन्होंने कहा जिला प्रशासन की तरफ से बरसाती मौसम दौरान किसी भी प्रकार की स्थिति के साथ निपटने के लिए पूरी तरह चौकस है और इस सम्बन्धित सभी जरूरी प्रबंध पहले ही पूरे किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अलग-अलग विभागों की तरफ से किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पहले ही व्यापक योजना बनाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ती है तो इन स्थानों में से लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए स्थानों की पहचान की जा चुकी है।

जिला प्रशासन की तरफ से मिशन फतेह के अंतर्गत 118500 लीटर दूध,700 किलो पनीर, 13032 किलो दही, 34657 लीटर लस्सी और 316 किलो खीर लोगों के घरों तक पहुँचाई

जालंधर/ब्यूरो

जिला प्रशासन ने आज मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से मिशन फतेह के अंतर्गत कोविड -19 महामारी से बचाव के लिए लगाए गए लाकडाऊन दौरान लोगों के घरों तक 118500 लीटर दूध और दूध से बने उत्पाद उपलब्ध करवाए। जनरल मैनेजर असिट शर्मा के नेतृत्व में मिलकफेड की टीमों की तरफ से जिले में अधिक से अधिक दूध और दूध के उत्पादों की सप्लाय की जा रही है। प्राप्त विवरणों के अनुसार मिलक 7 डी की टीमों की तरफ से आज 118500 लीटर दूध,700 किलो पनीर, 13032 किलो दही, 34657 लीटर लस्सी और 316 किलो खीर अलग-अलग आधोराईच डीलरों की तरफ से लोगों के घरों तक पहुँचायी गई। डिप्टी कमिशनर श्री घनश्याम थोरी ने बताया कि जिला प्रशासन वचनबद्ध है कि जिले में किसी को जरूरी चीजों की प्राप्ति के लिए कोई मुश्किल पेश न आए। कोविड -19 विरुद्ध पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से लोगों में कोरोना वायरस महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मिशन फतेह के अंतर्गत एक महौने तक चलने वाली मुहिम की पहली जून से शुरूआत की गई है।

पुलिस कमिशनरेट की तरफ से मिशन फतेह के अंतर्गत 13140 लोगों को मास्क न पहनने पर 59.15 लाख जुर्माना

जालंधर/ब्यूरो

मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से शुरू किये गए मिशन फतेह के अंतर्गत पुलिस कमिशनरेट जालंधर ने जानबूझ कर मास्क न पहनने वाले 13140 लोगों को 59.15 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।

इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए पुलिस कमिशनर श्री गुर्प्रीत सिंह भुखर ने बताया कि अब तक मास्क न पहनने वाले 13140 लोगों को 59.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस के इलावा होम कुआरंटिन का उल्लंघन करने वाले 40 व्यक्तियों को 71000 रुपए जुर्माना किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि जनक स्थानों पर थूकने वाले 302 व्यक्तियों को 40600 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। श्री भुखर ने आगे बताया कि अब तक 39509 ट्रैफिक चालान करके 2049 वाहनों को जब्त किया जा चुका है।

पुलिस कमिशनर ने आगे बताया कि पुलिस कमिशनरेट की तरफ से 55 चौपहिया वाहनों को ओवर लोडिड होने के कारण 102000 रुपए



और 32 आटो रिक्शा को ओवर लोडिड होने पर 16000 रुपए का जुर्माना किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 138 लोग को सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन करने पर 2,76,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आज पुलिस कमिशनरेट की तरफ से 187 ट्रैफिक चालान किये गए हैं।

उन्होंने बताया कि 171 लोगों को मास्क न पहनने पर चालान करके 85500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

श्री भुखर ने बताया कि इस मुहिम को आने वाले दिनों में भी जारी रखा जायेगा और उल्लंघन करने वालों खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी है।

उन्होंने कहा कि लोगों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोविड -19 महामारी से बचाएगा के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी निर्देशों की पूरी सख्ती से पालना की जाये।